International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और कनाडा में केंद्र एवं संघीय इकाइयों के बदलते संबंध।

सुमन[1]

शोधार्थी,राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक
maansuman30@gmail.com

डॉ०बी०प्रकाश[2]

शोध निर्देशक,प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक

सारांश :

वैश्वीकरण ने विश्व की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को बहुत प्रभावित किया है। इससे संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और संघीय इकाइयों (राज्यों और प्रांतों) के बीच संबंध भी बदल रहे हैं। भारत और कनाडा दोनों संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन उनका संविधान, राजनीतिक हालात और प्रशासनिक प्रणाली अलग हैं। वैश्वीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल शासन जैसे नए विषयों पर सहयोग और समन्वय की जरूरत को बढ़ा दिया है। जीएसटी , नीति आयोग, सहकारी संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों ने भारत में संघीय व्यवस्था को बदल दिया है। वहीं कनाडा में संघीय और राज्य सरकारों के बीच प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पर्यावरण और विदेशी व्यापार जैसे क्षेत्रों में समन्वय का महत्व बढ़ा है। वैश्वीकरण ने दोनों देशों में केंद्र सरकार की भूमिका को मजबूत किया है, साथ ही राज्यों और प्रांतों की नीतिगत भागीदारी और स्वायत्तता को भी महत्वपूर्ण बनाया है।

यह शोध पत्र वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत और कनाडा के केंद्रों और संघीय इकाइयों के बदलते संबंधों की तुलना करता है और संघीय व्यवस्था के सामने आने वाले चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करता है।

मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, प्रांतीय स्वायत्तता, सहकारी संघवाद, वित्तीय संघवाद, भारत, कनाडा।

प्रस्तावना :

वैश्वीकरण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं और प्रशासनिक प्रणालियों को एक-दूसरे से जोड़ने वाली आधुनिक विश्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, धन, तकनीक, सूचनाओं और विचारों का विश्वव्यापी व्यापार बढ़ा है। वैश्वीकरण ने न सिर्फ राष्ट्रीय सरकारों की प्रणाली को बदल दिया है, बल्कि संघीय सरकारों में केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच शक्ति-संतुलन को भी बदल दिया है। संघवाद एक प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें संवैधानिक रूप से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए, इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विविधता, आवश्यकताओं और हितों को उचित प्रतिनिधित्व देना है। कनाडा में संघीय इकाइयों को प्रांत कहा जाता है, लेकिन भारत में वे राज्य कहलाते हैं। वैश्वीकरण के विस्तार से केंद्रीय सरकारों को अंतरराष्ट्रीय निवेश, व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास की

नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा है। राज्यों और प्रांतों की भूमिका, दूसरी ओर, इन नीतियों को वास्तव में लागू करना भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस तरह, वैश्वीकरण ने संघवाद को केवल संवैधानिक शक्तियों के विभाजन तक सीमित नहीं किया है, बल्कि सहयोग, समन्वय और साझेदारी पर आधारित व्यवस्था में बदल दिया है।

इस मामले में, भारत और कनाडा का तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों में संघीय व्यवस्था है, लेकिन केंद्र और संघीय इकाइयों के संबंधों का रूप अलग है। भारत में केंद्र सरकार बहुत कम शक्तिशाली है, जबकि कनाडा में प्रांतीय सरकारों को बहुत अधिक संवैधानिक अधिकार हैं।

शोध समस्या :

वैश्वीकरण से भारत और कनाडा की संघीय सरकारों में पारंपरिक केंद्र-संघीय संबंध प्रभावित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, आर्थिक उदारीकरण और तकनीकी प्रगति ने केंद्र सरकारों की भूमिका बढ़ाई है। राज्यों और प्रांतों के बीच नीतिगत और प्रशासनिक सहयोग भी बढ़ा है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीतियों और संघीय इकाइयों की क्षेत्रीय आवश्यकताए अक्सर संघर्ष करती हैं। वित्तीय संसाधनों के वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक अधिकारों पर भी बहस होती है। जीएसटी व्यवस्था और भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध इस बदलाव के प्रमुख उदाहरण हैं। कनाडा में संघीय और राज्य सरकारों के बीच भी स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन और जलवायु नीति पर मतभेद हैं। यही कारण है कि यह अध्ययन वैश्वीकरण के प्रभाव से दोनों देशों के संघीय संबंधों में हुए बदलावों और शक्ति-संतुलन की प्रकृति को समझने की कोशिश करता है।

शोध के उद्देश्य :

- संघीय शासन पर वैश्वीकरण के प्रभावो का विश्लेषण करना।
- भारत में राज्यों और केंद्र के बदलते संबंधों का विश्लेषण करना।
- कनाडा में संघीय और राज्य सरकारों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना ।
- वैश्वीकरण से प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद में आए बदलाव को समझना ।
- भारत और कनाडा की संघीय प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
- संघीय इकाइयों और केंद्र के बीच सहयोग, समन्वय और शक्ति-संतुलन की चुनौतियों का विश्लेषण करना ।

शोध पद्धति :

यह शोध पत्र वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग करता है। यह अध्ययन अधिकांश द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों, संवैधानिक प्रावधानों, आयोगों की रिपोर्टों और कई संस्थाओं द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों का विश्लेषण शामिल है। भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके वैश्वीकरण के प्रभाव से केंद्र और संघीय इकाइयों के संबंधों में हुए बदलावों को समझने की कोशिश की गई है।

वैश्वीकरण और संघीय शासन व्यवस्था का संबंध :

वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, जो आज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, धन, तकनीक, सूचनाओं और विचारों का विश्वव्यापी व्यापार बढ़ा है। केंद्र सरकार और संघीय इकाइयों (राज्यों और प्रांतों) के बीच संबंध भी वैश्वीकरण से प्रभावित हुए हैं। संविधान संघीय शासन

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

व्यवस्था में केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच शक्तियों और अधिकारों का विभाजन करता है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के साथ-साथ क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन वैश्वीकरण के बढ़ने से शासन व्यवस्था में नए मुद्दे उत्पन हो गए हैं, जिनके समाधान के लिए संघीय और केंद्रीय निकायों के बीच सहयोग और समन्वय की जरूरत बढ़ गई है। निम्नलिखित संघीय शासन प्रणाली वैश्वीकरण से प्रभावित हुई हैं:-

- आर्थिक संबंधों में बदलाव: वैश्वीकरण ने व्यापार, निवेश और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया है। इससे राज्यों और प्रांतों की आर्थिक नीतियों और विकास संबंधी निर्णयों में समन्वय की आवश्यकता बढ़ गई है।
- वित्तीय संघवाद का उदय: केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच कर राजस्व, वित्तीय संसाधनों और अनुदानों का वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। आर्थिक विकास दोनों स्तरों की सरकारों पर निर्भर हो गया है I
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: राष्ट्रीय सरकारें वैश्विक चुनौतियों को हल नहीं कर सकतीं। इसलिए, संघीय इकाइयों और केंद्र के बीच संवाद, सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता बढ़ी है।
- प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन: ई-गवर्नेंस, डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन सेवाओं की वृद्धि ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बदल दिया है। केंद्र और राज्य को इन व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक और तकनीकी समन्वय की जरूरत है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: राज्यों और प्रांतों की भूमिका वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो गई है।
- पर्यावरणीय चुनौतियो का प्रभाव: केंद्र और संघीय इकाइयों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए।
- स्थानीय स्वायत्तता और नियंत्रण: वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और नीतिगत निर्णयों का महत्व बढ़ा दिया है, लेकिन संघीय निकायों की भूमिका भी इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण हो गई है। इससे राज्यों और केंद्र के अधिकारों और स्वायत्तता पर नए प्रश्न उठ गए हैं।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद की व्यापकता: विभिन्न राज्य और प्रांत वैश्विक निवेश और आर्थिक अवसरों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसने प्रशासनिक नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है।

भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में केंद्र एवं राज्यों के बदलते संबंध :

1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद, राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों में बड़ा बदलाव हुआ है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों ने भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा है I इससे राज्यों की भूमिका प्रशासनिक इकाइयों से बाहर निकलकर आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन का प्रमुख केंद्र बन गई है।

(i) आर्थिक उदारीकरण और राज्यों का बढ़ा हुआ योगदान -

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है I विभिन्न राज्यों ने औद्योगिक विकास, बिजली, परिवहन, आधारभूत संरचना और

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

व्यापारिक सुविधाओं में सुधार करके निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की। इससे राज्यों की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता और महत्त्व बढ़ गया है।

(ii) सहकारी संघवाद की वृद्धि -

भारत में सहकारी संघवाद की विचारधारा ने केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को एक नया रूप दिया है। राष्ट्रीय विकास के लिए दोनों स्तरों की सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय बनाये रखना इसका लक्ष्य है। नीति आयोग की स्थापना ने राज्यों और केंद्र के बीच नीतिगत चर्चा को बढ़ा दिया है। राज्यों की आवश्यकताओं और सुझावों को नीति निर्माण में महत्व देने का प्रयास किया गया है।

(iii) जीएसटी का प्रभाव:

2017 में वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से भारतीय वित्तीय संघवाद में बड़ा बदलाव आया। जीएसटी ने राज्यों और केंद्र सरकारों की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक संयुक्त ढाँचे में लाने की कोशिश की। जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्रों दोनों को प्रतिनिधित्व मिला है। इससे कर दरों और कर नीतियों पर एकीकृत निर्णय लिया जाता है।

जीएसटी ने कर प्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, लेकिन इससे राज्यों को कर निर्धारण करने की स्वतंत्रता में कमी आई है। इसलिए जीएसटी भारतीय संघवाद और वित्तीय स्वायत्तता के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

(iv) वित्तीय संघवाद का विकास:

वैश्वीकरण ने राज्यों को विकास की अधिक जिम्मेदारी दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों को कर राजस्व का हिस्सा और अनुदान देती है। इसके बावजूद, राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व और व्यय में असंतुलन है।

(v) डिजिटल प्रशासन और संबंध:

डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने सरकारी व्यवस्था को बदल दिया है। केंद्र और राज्यों को इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग करना चाहिए। हालाँकि, डिजिटल सुविधाओं को विकसित करने में राज्यों की आर्थिक और तकनीकी क्षमता में असमानता भी दिखाई देती है।

(vi) जलवायु और पर्यावरणीय बदलाव:

भारत में, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय का महत्व बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, वन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी योजनाओं की आवश्यकता हैं।

कनाडा में वैश्वीकरण के संदर्भ में संघीय एवं प्रांतीय संबंधों में परिवर्तन :

कनाडा एक संघीय देश है, जहाँ संवैधानिक रूप से संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारें अलग-अलग काम करती हैं। 1867 के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम—वर्तमान में जिसे संविधान अधिनियम, 1867 कहा जाता है—कनाडा के संघवाद का मूल आधार था। कनाडा के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों को वैश्वीकरण ने बदल दिया है। प्रांतीय सरकारें और आर्थिक वैश्वीकरण : कनाडा की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश पर अधिक निर्भर है।प्रांतीय सरकारों की आर्थिक भूमिका वैश्वीकरण के कारण बढ़ी है। विभिन्न राज्यों ने अपनी आर्थिक विकास की नीतियाँ अपने प्राकृतिक

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

संसाधनों, औद्योगिक क्षमताओं और भूगोल के आधार पर बनाई हैं। उदाहरण के लिए, अल्बर्टा अपने प्राकृतिक गैस और तेल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ओंटारियो का औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। इससे प्रांतीय सरकारों की आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आर्थिक नीति में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

(i)विदेशी व्यापार और राष्ट्रीय संबंध-

कनाडा की संघीय सरकार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन राज्यों की कृषि, उद्योग, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों पर भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का असर पड़ता है। इसलिए प्रांतीय सरकारों से परामर्श लेना अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जरूरी हो गया है।

(ii)राज्य स्वायत्तता और वित्तीय संघवाद-

कनाडा में प्रांतीय सरकारों को कर लगाने और राजस्व प्राप्त करने का व्यापक अधिकार है। समानता अनुदान और वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से संघीय सरकार आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। वैश्वीकरण ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक विकास से कुछ प्रांत आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जबकि अन्य प्रांत संघीय धन पर अधिक निर्भर हैं।

(iii)शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंध-

कनाडा में प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन संघीय सरकार इन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय मानकों और कार्यक्रमों के माध्यम से काम करती है। दोनों स्तरों की सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बाजार में सुधार के लिए मिलकर काम किया है, क्योंकि वैश्वीकरण और जनसंख्या की बदलती आवश्यकताओं ने दोनों स्तर की सरकारों में सहयोग को बढ़ा दिया है।

(iv)प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण-

कनाडा की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। खनन, तेल और गैस उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में प्रांतीय सरकारें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन जैसे विश्वव्यापी मुद्दों से निपटने के लिए संघीय सरकार राष्ट्रीय नीतियां बनाती है। इसलिए प्रांतीय आर्थिक हितों और संघीय पर्यावरण नीतियों में अक्सर मतभेद देखने को मिलते हैं I

(v)बहुसांस्कृतिक समाज और क्षेत्रीय पहचान-

संघीय व्यवस्था में कनाडा की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, क्यूबेक प्रांत अपनी फ्रांसीसी भाषा और सांस्कृतिक पहचान को बचाने पर बहुत ध्यान देता है। प्रांतीय सरकारों की भूमिका सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों के निर्माण में बढ़ी है, क्योंकि वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संपर्क और प्रवासन को बढ़ावा दिया है।

भारत और कनाडा में केंद्र एवं संघीय इकाइयों के संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन :

भारत और कनाडा में संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें संवैधानिक रूप से केंद्र और संघीय निकायों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। कनाडा में संघीय इकाइयों को प्रांत कहा जाता है, लेकिन भारत में वे राज्य कहलाते हैं। कनाडा में प्रांतीय सरकारों को बहुत अधिक संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन भारत में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ,

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

राज्य और समवर्ती सूची हैं। संविधान अधिनियम, 1867 ने कनाडा में सरकारी अधिकारों को विभाजित किया है। संघीय सरकार दोनों देशों को अतिरिक्त अधिकार देती है। जीएसटी परिषद और वित्त आयोग भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि कनाडा में संघीय सरकार प्रांतों को वित्तीय हस्तांतरण और समानता प्रदान करती है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची पर आधारित है, जबकि कनाडा में शिक्षा मुख्यतः प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में आती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दोनों देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग हैं। वैश्वीकरण ने दोनों देशों में विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में संघीय संस्थाओं की भूमिका को बढ़ा दिया है। जबकि कनाडा में राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक क्षमताओं पर निर्भर करके विकास नीतियाँ बनाते हैं, भारत में राज्यों के बीच औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। दोनों देशों में आर्थिक विकास, डिजिटल शासन और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और संघीय निकायों के बीच समन्वय की जरूरत है। इस तरह, भारत में केंद्र-प्रधान संघवाद है, जबकि कनाडा में प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित संघवाद है। फिर भी, वैश्वीकरण के दौर में दोनों देशों में सहयोग, समन्वय और शक्ति-संतुलन का महत्व बढ़ता जा रहा है।

वैश्वीकरण के कारण भारत और कनाडा के संघीय संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव :

- वैश्वीकरण ने प्रशासनिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है।
- राज्यों और प्रांतों में आर्थिक विकास की नई संभावनाएँ विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से पैदा हुई हैं।
- संघीय इकाइयों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास नीतियाँ बनाने के अधिक अवसर मिल गए हैं।
- डिजिटल शासन और तकनीकी विकास ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ा दी है।
- विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच नीतिगत संवाद बढ़ा है और सहकारी संघवाद की भावना बढ़ी है।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

वैश्वीकरण के कारण संघीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव एवं चुनौतियाँ :

- वैश्वीकरण के कारण केंद्र सरकार की नीतिगत और आर्थिक शक्ति का विस्तार संघीय इकाइयों की स्वायत्तता को कम कर सकता है।
- वित्तीय संसाधनों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का कारण बनता है।
- विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों और प्रांतों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।
- क्षेत्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय नीतियों को तालमेल में लाना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का स्थानीय उद्योगों और कृषि क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव हो सकता है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास के कारण विकसित और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल असमानता बढ़ सकती है।

संघीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सुझाव :

भारत और कनाडा में संघीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संघीय इकाइयों और केंद्रों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना चाहिए। राज्यों और प्रांतों के संवैधानिक अधिकारों और स्वायत्तता का

सम्मान किया जाना चाहिए। संसाधनों का पारदर्शी और उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। संघीय संस्थाओं को राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी निवेश और आर्थिक वृद्धि के अवसरों को हर क्षेत्र में पहुंचाना चाहिए। डिजिटल विकास और पर्यावरण संरक्षण में मिलकर काम करना चाहिए। संघीय मतभेदों को आपसी चर्चा से हल करना चाहिए। अंततः राष्ट्रीय स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलित करना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत और कनाडा में केंद्रीय और संघीय इकाइयों के संबंधों को वैश्वीकरण ने नया रूप दिया है। आर्थिक वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तकनीक का विकास और पर्यावरण संरक्षण के कारण दोनों देशों में आपसी सहयोग और समन्वय का महत्व बढ़ा है। कनाडा में प्रांतीय स्वायत्तता अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि भारत में केंद्र सरकार की भूमिका अधिक है। शक्ति-संतुलन, वित्तीय न्याय और क्षेत्रीय स्वायत्तता, वैश्वीकरण के दौर में संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इसके साथ ही राज्यों और प्रांतों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का प्रोत्साहन भी आवश्यक है। नीतिगत मतभेदों और प्रशासनिक समस्याओं को केंद्र और संघीय इकाइयों के बीच बेहतर संवाद से हल किया जा सकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और समान विकास अवसर देने पर दोनों देशों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अंततः, मजबूत संघवाद के लिए राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय स्वायत्तता और सहयोग को संतुलित करना चाहिए।

संदर्भ सूची :

- सक्सेना, रेखा. (2012). संघवाद की स्थिति: भारत और कनाडा में अंतर-सरकारी संबंधों के तंत्र। नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स।
- ह्यूगलिन, थॉमस ओ. एवं फेना, एलन. (2015). तुलनात्मक संघवाद: एक व्यवस्थित अध्ययन। टोरंटो विश्वविद्यालय प्रेस।
- वाट्स, रोनाल्ड एल. (2008). संघीय व्यवस्थाओं की तुलना। मैकगिल-क्वीन्स यूनिवर्सिटी प्रेस।
- बर्गेस, माइकल. (2006). तुलनात्मक संघवाद: सिद्धांत एवं व्यवहार। रूटलेज।
- ओट्स, वालेस ई. (1972). राजकोषीय संघवाद। हार्कोर्ट ब्रेस जोवानोविच।
- मुसग्रेव, रिचर्ड ए. (1959). सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत। मैकग्रा-हिल।
- भारत सरकार. भारत का संविधान। विधायी विभाग, नई दिल्ली।
- भारत सरकार. (2023). आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारत सरकार. वित्त आयोग की रिपोर्ट। नई दिल्ली।
- नीति आयोग. सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद संबंधी रिपोर्ट। नई दिल्ली।
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद. जीएसटी से संबंधित रिपोर्ट एवं दस्तावेज। भारत सरकार।
- कनाडा सरकार. कनाडा का संविधान अधिनियम, 1867 एवं 1982। ओटावा।
- कनाडा सरकार. संघीय एवं प्रांतीय संबंधों से संबंधित दस्तावेज। ओटावा।
- ओट्स, वालेस ई. (1999). राजकोषीय संघवाद पर एक निबंध। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 37(3), 1120–1149।
- सिंह, निर्विकार एवं श्रीनिवासन, टी. एन. (2004). भारतीय संघवाद, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण।
- फोरम ऑफ फेडरेशन्स. संघीय व्यवस्था एवं अंतर-सरकारी संबंधों से संबंधित अध्ययन।
- भारतीय रिजर्व बैंक. राज्य वित्त: बजट का अध्ययन। मुंबई।

- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD). (2024). राजकोषीय संघवाद में सहयोग एवं समन्वय संबंधी अध्ययन।
- भारत सरकार. (1991). नई आर्थिक नीति एवं आर्थिक उदारीकरण संबंधी दस्तावेज। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।